



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 2016/ ज्येष्ठ 16, 1938

No. 239]

NEW DELHI MONDAY, JUNE 6, 2016/JYAISTHA 16, 1938

### महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 20 मई, 2016

सं टीएमपी/62/2009-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार पारादीप पत्तन न्यास के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार करता है।

### महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

संख्या. टीएमपी/62/2009-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्याय

— — —

आवेदक

### गणपूर्ति

- (i). श्री टीएस. बालसुब्रमनियन (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

### आदेश

(मई, 2016 के 6ठे दिन पारित)

यह आदेश पारादीप पत्तन न्याय (पीपीटी) के मौजूदा दरमानों की वैधता को विस्तारित करने से संबंधित है।

2.1 पीपीटी का मौजूदा दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/62/2009पीपीटी दिनांक 25 मार्च, 2011 द्वारा अनुमोदित किया था जिसे 23 मई 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस आदेश ने दरमान की वैधता 31 मार्च 2013 तक निर्धारित की थी।

2.2 हमारे 10 जनवरी, 2014, 4 अप्रैल, 2014, 4 जुलाई, 2014, 30 सितम्बर, 2014 और 2 जनवरी, 2015 के आदेशों द्वारा आवधिक अंतरालों पर उक्त आदेशों में अभिलेखबद्ध किए गए कारणों से आवधिक अंतराल पर विस्तार किया था। प्रत्येक अवसर पर वैधता का विस्तार करते समय पीपीटी को इस प्राधिकरण द्वारा सामान्य संशोधन प्रस्ताव तत्काल दायर करने की सलाह दी गई।

2.3 इसी बीच 13 जनवरी, 2015 से महापत्तन न्यासों के लिए लागू प्रशुल्क नीति, 2015 प्रभावी हो गई है। फलस्वरूप, जैसा कि प्रशुल्क नीति के खंड 1.5 में अनुबद्ध है, इस प्राधिकरण ने जून, 2015 में उक्त प्रशुल्क नीति, 2015 को प्रचालनात्मक करने के लिए कार्यकारी दिशानिर्देश जारी किए थे। पीपीटी को नई प्रशुल्क नीति, 2015 के अनुसार संशोधित प्रस्ताव दायर करने की सलाह दी गई थी। उसी समय, प्रशुल्क में निर्वात से बचने के लिए, इस प्राधिकरण ने नियमित अंतराल पर पीपीटी के मौजूदा दरमानों में विस्तार किया।

3.1 इस पृष्ठभूमि में पीपीटी को 06 अप्रैल, 2016 को अ0स0प0 के द्वारा प्रशुल्क नीति, 2015 के अनुसार सामान्य संशोधन प्रस्ताव शीघ्र दायर करने का स्मरण कराया गया।

3.2 प्रत्युत्तर में अध्यक्ष, पीपीटी ने सदस्य (वित्त) को संबोधित अपने 25 अप्रैल, 2015 के अ0स0 पत्र में निम्नलिखित निवेदन किए :

- i. पिछले दरमान संशोधन के दौरान 2011 में 32 प्रतिशत की घटौती हुई थी। इसका पत्तन के प्रचालन अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- ii. आरएफडी को अंतिम रूप देने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक में प्रचालन अनुपात को 57 प्रतिशत के स्तर पर बनाये रखने का निर्णय लिया गया था। इसलिये, मौजूदा प्रशुल्क को संशोधित न करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, पीपीटी ने दरमानों में कोई संशोधन नहीं किया और वही दर जारी है।
- iii. पीपीटी से दरमानों में और संशोधन करने पर जोर न दिया जाए और वही कम से कम 31 मार्च 2017 तक जारी रखे जाएं।
- iv. तथापि, पीपीटी द्वारा उन्हीं दरमानों को जारी रखने का संशोधित प्रस्ताव एक महीने की अवधि में भेज दिया जायेगा।

4. पीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता पहले ही 31 मार्च 2016 को समाप्त हो गई है। पीपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव (दायर किया जाना है) के प्रसंस्करण में लगने वाले समय और पीपीटी के दरमानों में निर्वात से बचने को ध्यान में रखकर पीपीटी के मौजूदा दरमानों की 16 मार्च 2016 से आगे की अवधि के लिए विस्तार किए जाने की अपेक्षा है।

5. उक्त स्थिति को देखते हुए यह प्राधिकरण, पीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार 30 सितम्बर, 2016 तक करता है। पीपीटी को पत्तन द्वारा स्वीकार की गई समय सीमा के भीतर अपना प्रस्ताव

दायर करने की सलाह दी जाती है। 1 अप्रैल, 2013 के बाद से पीपीटी के अतिरिक्त अतिरेक यदि कोई है, को नई महापत्तन न्यास संबंधी प्रशुल्क नीति, 2015 के द्वारा अधिशासित किया जायेगा।

टी.एस.बालसुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/16(120)]

## **TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION**

**No. TAMP/62/2009PPT.**—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust as in the Order appended hereto.

### **Tariff Authority for Major Ports**

Case No.TAMP/62/2009-PPT

**The Paradip Port Trust**

---

**Applicant**

### **QUORUM**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

### **O R D E R**

(Passed on this 6<sup>th</sup> day of May 2016)

This Order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust (PPT).

2.1. The existing Scale of Rates (SOR) of PPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/62/2009-PPT dated 25 March 2011 which was notified in the Gazette of India on 23 May 2011. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2013.

2.2. The validity of the SOR was extended by this Authority at periodic intervals vide Orders dated 10 January 2014, 4 April 2014, 4 July 2014, 30 September 2014 and 2 January 2015 for the reasons recorded in the said Orders. While extending the validity at each occasion, the PPT was advised by this Authority to file the general revision proposal immediately.

2.3. In the meanwhile, the Tariff Policy, 2015, applicable for Major Port Trusts has come into effect from 13 January 2015. Consequently, as stipulated in Clause 1.5 of the Tariff Policy, this Authority in June 2015 has issued the Working Guidelines to operationalize the said Tariff Policy, 2015. The PPT was advised to file a revised proposal in accordance with the new Tariff policy of 2015. At the same time, to avoid a vacuum in the tariff, this Authority has, on regular intervals, extended the validity of the existing SOR of PPT. On the last occasion, the validity of the existing SOR of PPT has been extended till 31 March 2016.

3.1. In this backdrop, PPT was reminded vide a d.o letter dated 06 April 2016, to expedite filing of the general revision proposal of PPT as per Tariff Policy, 2015.

3.2. In response Chairman PPT, vide his d.o. letter dated 25 April 2016 addressed to Member (Finance) has made the following submissions:

- (i). During the last SOR revision, there was a reduction of 32% in 2011. This had an adverse effect on the Operating Ratio of the Port.
- (ii). In the meeting held by the Ministry of Shipping (MOS) for finalizing the RFD, it was agreed to maintain the operating ratio at the level of 57%. It was accordingly decided not to revise the existing tariff. Accordingly, the SOR of PPT was not revised and the same rates continued.

- (iii). Further revision of SOR of PPT may not be insisted upon and the same SOR may continue at least up to 31 March 2017.
- (iv). However, a revised proposal for continuing with the same SOR will be sent by PPT within a month's time.

4. The validity of the existing SOR of PPT has already expired on 31 March 2016. Considering the time required for processing the proposal (to be) filed by the PPT and in order to avoid a vacuum in the SOR of PPT, the validity of the existing SOR of PPT needs to be extended for the period beyond 31 March 2016.

5. In view of the above position, this Authority extend the validity of the existing SOR of PPT up to 30 September 2016. The PPT is advised to file its proposal positively within the time limit agreed by the port. The treatment of additional surplus, if any, accruing to the PPT for the period beyond 1 April 2013 will be governed by the new Tariff Policy for Major Port Trusts, 2015.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)  
[ADVT.-III/4/EXTY./143/16(120)]